NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
सितंबर 2025, नई दिल्ली

युवाओं को उद्यमी बनाने की सफल यात्रा

एनवाईसीएस की स्थापना के 25 साल बेमिसाल

अंदर के पन्नों पर

- अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन नवंबर में
- जीएसटी कटौती से सहकारी संस्थाएं होंगी मजबूत

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-03, सितंबर-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, एट्बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जीएम ऑफसेट, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

ऊंची उड़ान भरने को तैयार एनवाईसीएस 04
कोऑपरेटिव बैंकों का बढ़ेगा नेटवर्क 05

06 युवाओं को उद्यमी बनाने की सफल यात्रा

16 एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में एनवाईसीएस की रही मजबूत भागीदारी

एनसीडीसी के प्रोत्साहन से मजबूत हो रही कोऑपरेटिव्स 20
ट्रम्प टैरिफ से रोजगार पर संकट 24
आदिवासी मुख्यमंत्री ने जगाया भरोसा, बदल रहा बस्तर 26
एक इम्तिहान पास कर बाकी दो की तैयारी में जुटी हॉकी टीम 28
युवाओं की नौकरी के लिए निजी कंपनियों से एमओयू 30

ऊंची उड़ान भरने को तैयार एनवाईसीएस

एनवाईसीएस की वार्षिक आम सभा (एजीएम) में यह तय किया गया कि अब संगठन नए जोश के साथ नए-नए लक्ष्य निर्धारित करेगा और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने में अपना योगदान बढ़ाएगा। चूंकि युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, इसलिए युवाओं की संस्था होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की स्थापना को 25 वर्ष हो चुके हैं। दिसंबर में यह 26 वर्ष का हो जाएगा। यह यात्रा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। इस लंबी यात्रा में संगठन ने हजारों युवाओं को एन्टरप्रेन्योर बनने में मदद की है, 60 हजार से ज्यादा ऐसे युवाओं का रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास किया है जिनके पास कोई कौशल नहीं था और करीब 5 लाख युवाओं को करियर काउंसलिंग एवं खेल जैसे अन्य क्षेत्रों के माध्यम से अपना भागीदार बनाया है। युवा सशक्तीकरण की दिशा में एनवाईसीएस की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक पड़ाव है।

22 अगस्त को हुई एनवाईसीएस की वार्षिक आम सभा (एजीएम) में यह तय किया गया कि अब संगठन नए जोश के साथ नए-नए लक्ष्य निर्धारित करेगा और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने में अपना योगदान बढ़ाएगा। चूंकि युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, इसलिए युवाओं की संस्था होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है। इसे देखते हुए ही एनवाईसीएस ने इसी साल नवंबर में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका विषय 'युवा सहकार: विकसित भारत' का आधार रखा गया है। सम्मेलन के माध्यम से एनवाईसीएस की पहचान न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी, बल्कि संगठन को अगले स्तर पर ले जाने में भी इसकी बड़ी भूमिका होगी। यह देश के युवाओं को सहकारिता से जोड़ने का एक बेहतर माध्यम भी बनेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, उसमें एनवाईसीएस का क्या योगदान होगा, अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन में इस पर भी मंथन किया जाएगा। सहकारिता एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है जो भारत के व्यापक विकास का सपना पूर्ण कर सकता है। इसमें असीमित क्षमता है और इसके माध्यम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जरूरत है, इसकी संभावनाओं की पहचान और उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की।

एनवाईसीएस का नेटवर्क देश के 603 जिलों में फैला हुआ है। इसका व्यापक नेटवर्क ही इसका असली नेटवर्थ है। इस नेटवर्क से सतीश मराठे, ज्योतिंद्र मेहता जैसे सहकारिता दिग्गज सहित वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे राष्ट्रीय नेता जुड़े रहे हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री वी. मुरलीधरन तो संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ही रहे हैं। इनके अलावा केंद्रीय और राज्य स्तर पर सैकड़ों ऐसे दिग्गज हैं जिनका सानिध्य हमारी सफलता में सहायक बना है। संगठन को नई ऊंचाई पर ले जाने में आगे भी उनका सहयोग मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ हमने विकसित भारत बनाने की यात्रा में अपना कदम बढ़ा दिया है। ■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

कोऑपरेटिव बैंकों का बढ़ेगा नेटवर्क

युवा सहकार टीम

वंचित क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों तक कोऑपरेटिव बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय इनके नेटवर्क के विस्तार की योजना बना रहा है। नाबार्ड ने देशभर में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग की पहुंच को व्यापक बनाने के निर्णायक प्रयास के तहत एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। मंत्रालय ने इस पत्र को सभी राज्य सरकारों को फीडबैक और कार्रवाई के लिए भेजा है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण आबादी वित्तीय समावेशन के दायरे में आ सकें।

नाबार्ड ने अपने दृष्टिकण पत्र में वंचित क्षेत्रों के लिए 240 नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और दो राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के गठन की सिफारिश की है। इसमें इनकी स्थापना की विस्तृत योजना पेश की गई है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर (एसटीसीसीएस) की कमियों को पाटना है। वर्तमान में देश के 615 जिलों में से 573 जिलों में 351 डीसीसीबी कार्यरत हैं और 42 जिले इनसे वंचित रह गए हैं। इनमें से 38 जिलों में राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन समर्पित डीसीसीबी का अभाव है। जबकि चार जिले (झारखंड में तीन और उत्तर प्रदेश में एक) राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं और डीसीसीबी दोनों से पूरी तरह वंचित हैं।

नाबार्ड के इस पत्र में कहा गया है कि दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और लक्षद्वीप में सहकारी बैंकिंग बुनियादी ढांचा नहीं है। इसलिए यहां एसटीसीबी की स्थापना की जाए ताकि दो-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से सहकारी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच हो सके। नए बैंक बनाने के प्रस्तावों के अलावा यह अप्रोच पेपर राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के गठन को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक वैधानिक और नियामक दिशानिर्देशों को समेकित करता है। यह रोडमैप राज्य सरकारों को सहकारी ऋण संरचना का कुशलतापूर्वक विस्तार करते हुए नियामकीय अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है।

240 नए डीसीसीबी बनाने की योजना सहकारिता क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी। इससे डीसीसीबी नेटवर्क में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इस विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण भारत के वित्तीय संकट को दूर करना है। सहकारी बैंक पारंपरिक रूप से जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कर्ज प्रवाह को सुगम बनाते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मौजूदगी से सहकारी बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगी। सहकारिता मंत्रालय के राज्य सरकारों से सुझाव मांगने से इस दृष्टिकोण पत्र के कार्यान्वयन में तेजी आ सकती है और सहकारी आंदोलन को बल मिल सकता है।■

नाबार्ड ने 240 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और दो राज्य सहकारी बैंक के गठन का रखा प्रस्ताव

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों से मांगे सुझाव, सहकारी बैंकिंग सेवा से जुड़ेंगे वंचित क्षेत्र

एनवाईसीएस की स्थापना के 25 साल बेमिसाल

युवाओं को उद्यमी बनाने की सफल यात्रा

पच्चीस वर्ष की अपनी यात्रा में एनवाईसीएस ने हजारों युवा उद्यमी किए तैयार

60 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए दिया प्रशिक्षण

अभिषेक राजा

सहकारिता के माध्यम से युवाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करने के लिए दिसंबर 1999 में जब नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की स्थापना की गई थी, तब शायद ही इसके संस्थापकों ने सोचा होगा कि यह युवाओं की बड़ी कोऑपरेटिव सोसायटी में से एक बन जाएगी। नेटवर्थ के मामले में भले ही यह बड़ी न हो, लेकिन नेटवर्क के मामले में यह देशभर में फैल चुकी है। देश के 600 से ज्यादा जिलों में संगठन के प्रतिनिधि और सदस्य मौजूद हैं। यही व्यापक नेटवर्क इसके संचालन का आधार है। एनवाईसीएस के संस्थापकों में इसके संस्थापक अध्यक्ष वी. मुरलीधरन जो 2019 से 2024 तक विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रहे, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज सतीश मराठे जैसे लोग रहे हैं। इनके अलावा मौजूदा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जैसे राजनीतिज्ञ भी एनवाईसीएस के दो बार डायरेक्टर रह चुके हैं। युवाओं की इस सहकारी संस्था ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं या यूं कहें कि यह संस्था अब जवान हो चुकी है और आगे का सफर तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

एनवाईसीएस की भविष्य की गतिविधियों को लेकर 22 अगस्त को हुई वार्षिक आम सभा (एजीएम) में विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में 22 राज्यों से आए संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। एजीएम को संबोधित करते हुए एनवाईसीएस के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू ने कहा, 'सहकारिता के माध्यम से युवाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करने के उद्देश्य से नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी का गठन किया गया। उस समय जिन लोगों ने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने पहले ही यह भांप लिया था कि आने वाले वर्षों में देश के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए क्या जरूरी है। इस संस्था का जन्म गैर डिजिटल और गैर इंटरनेट एरा में हुआ था, जिसके बिना आज जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। तब संस्थापकों की इसके भविष्य को लेकर क्या सोच थी यह तो पता नहीं, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब जरूर हुए। अपने शुरुआती दिनों में इस संस्था ने बुक लॉन्चिंग से लेकर केरल में ड्राई फिश बेचने और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जरिये यूथ डेवलपमेंट जैसे हर तरीके के काम किए।' 25 वर्षों की अपनी यात्रा में एनवाईसीएस ने युवा सशक्तीकरण से जुड़े बहुत सारे काम किए हैं। इस दौरान संगठन ने हजारों लोगों को एन्टरप्रेन्योर बनने में मदद की है, युवा उद्यमियों को तैयार किया है और ऐसे युवा जिनके पास रोजगार और स्वरोजगार के लिए कोई कौशल नहीं था, उनका कौशल विकास कर उनकी जिंदगी को संवारने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार रहा है।

आगे बढ़ने को तैयार

एनवाईसीएस प्रेसीडेंट ने एजीएम में मौजूद जिला और राज्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए उन्हें संगठन का बेहतर नेतृत्वकर्ता बताया। उन्होंने कहा, 'हम भाग्यशाली हैं कि अब हम ऐसे समय में हैं जब भारत सरकार ने सहकारिता का महत्व समझते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और सहकारिता के माध्यम से देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवाओं और गांवों का सशक्तीकरण किए बगैर विकसित भारत का

संगठन ने हजारों लोगों को एन्टरप्रेन्योर बनने में मदद की है, युवा उद्यमियों को तैयार किया है और ऐसे युवा जिनके पास रोजगार और स्वरोजगार के लिए कोई कौशल नहीं था, उनका कौशल विकास कर उनकी जिंदगी को संवारने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार रहा है।

कवर स्टोरी

कवर स्टोरी

लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है। शुरुआती 10 वर्षों में इस संगठन ने काफी संघर्ष किया है। आज हम जिस मुकाम पर हैं यह उन्हीं संघर्षों का नतीजा है। भविष्य को लेकर हम काफी आशावान हैं, इसलिए समय के साथ तालमेल बैठाते हुए संगठन ने खुद में बदलाव किया है और आगे बढ़ने को प्रेरित हुए हैं।'

यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए एनवाईसीएस नवंबर महीने में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से न सिर्फ भारतीय सहकारिता की गूंज दुनिया सुनेगी, बल्कि एनवाईसीएस की पहचान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनेगी और संगठन को अगले स्तर पर ले जाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। यह देश के युवाओं को सहकारिता से जोड़ने का एक बेहतर माध्यम भी बनेगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा राज्यों के सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित देशभर के युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं

विश्व में भारत एक सशक्त युवा देश के रूप में उभरा है। देश की कुल जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अगले दो दशक तक कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। युवाओं को कुशल बनाकर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने की बड़ी चुनौती है। देश के विकास में इस युवा आबादी के सकारात्मक योगदान और अर्थव्यवस्था के साथ उसे जोड़ने की पर्याप्त संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए देश की युवा शक्ति की ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए आवश्यक होगा कि युवाओं के लिए बेहतर संभावनाओं वाले क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सहकारी क्षेत्र इस मामले में एक नए सेक्टर के रूप में सामने आया है।

सहकारिता एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है जो भारत के व्यापक विकास का सपना पूर्ण कर सकता है। इसमें समाज की निचली इकाई ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय विकास की धुरी बनते हुए विकसित भारत का आधार बनने की क्षमता है। जरूरत है, इसकी संभावनाओं की पहचान और उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की। इसी उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए एनवाईसीएस अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसका मकसद युवाओं को सहकारिता क्षेत्र से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, उन्हें जागरूक बनाकर बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नए द्वार खोलना, तकनीक के इस्तेमाल से सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ-साथ सहकारिता कैसे गांव-समाज और देश का विकास कर सकती है, इसकी संभावनाओं को तलाशना है।

एनवाईसीएस के पास बेहतर मौका

एजीएम को एनवाईसीएस की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन राजेश पांडे ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'नवंबर में अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का थीम 'युवा सहकारः विकसित भारत का आधार' रखा गया है जिसमें 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे।' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है उसे साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और यह सबसे युवा देश है। अगले एक दशक तक भारत इसी तरह युवाओं का देश बना रहेगा।

क्या है एनवाईसीएस

एनवाईसीएस एक मल्टीस्टेट, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी है। यह युवाओं को विभिन्न रोजगार या स्व-रोजगार संबंधी गतिविधियों में संलग्न कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में कार्य करती है। 1999 में स्थापित यह संगठन बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत है। एनवाईसीएस की मुख्य गतिविधियों में युवाओं को सुविधा प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह बनाना, उद्यमिता विकास और युवाओं एवं अन्य हितधारकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्षमता निर्माण करना है। एनवाईसीएस अपनी स्थापना के बाद से देश भर में उद्यमियों के विकास और पोषण पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इसका देश के 603 जिलों में एक मजबूत नेटवर्क है जिसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाती है और उन्हें उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें बहीखाता पद्धति, मार्केटिंग कौशल, सॉफ्ट स्किल, प्रबंधकीय कौशल, टीम प्रबंधन, नेतृत्व प्रबंधन और जीवन कौशल शामिल हैं। एनवाईसीएस का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगारोन्मुखी और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए युवा सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाता है।

NYCS

एनवाईसीएस की गतिविधियां और उपलब्धियां

सीएसआर परियोजनाएं

एनवाईसीएस-कोविडा ने बार्टी (बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ विभिन्न सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) परियोजनाएं शुरू की हैं। वित्त वर्ष 23-24 तक सीएसआर परियोजनाओं के तहत 5,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

पीएमकेवीवाई

एनवाईसीएस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में प्रशिक्षण साझेदार है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिले। इसके तहत एनवाईसीएस ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं की काउंसलिंग की है और 50,000 से ज्यादा को ट्रेनिंग दी है।

कौशल्या सेतु अभियान

एसएससी परीक्षा पास करने में कठिनाई का सामना करने वाले छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चलाई जा रही 'कौशल्या सेतु अभियान' परियोजना में एनवाईसीएस कार्यान्वयन भागीदार है। इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के हाई स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के 34 जिलों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यान्वित की गई है।

पूर्व-शिक्षण मान्यता परियोजना

यह अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को मान्यता प्रदान करने का एक मंच है, ताकि औपचारिक शिक्षा के समान ही स्वीकृति मिल सके। इसके तहत एनवाईसीएस ने ओला चालकों और टैक्सी, ऑटो-रिक्शा तथा वाणिज्यिक वाहनों के अन्य स्थानीय चालकों सहित 6,000 चालकों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा कर लिया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पांच शहरों लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और नोएडा में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें 1500 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जैव ऊर्जा उत्सव

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एनवाईसीएस और महरत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से जुलाई 2017 में शिव छत्रपति क्रीड़ानगरी, बालेवाड़ी और पुणे में एक विशाल कार्यक्रम 'जैव ऊर्जा उत्सव' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालना था ताकि एक समावेशी राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा विकसित किया जा सके। एनवाईसीएस ने 10 अगस्त, 2017 को देश भर के 100 स्थानों पर जैव ऊर्जा कार्यक्रम आयोजित करके विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया।

रिसर्जेंट इंडिया युवा कॉन्क्लेव

युवाओं का सशक्तीकरण करने वाले इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य आने वाले दशक में युवाओं के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इस कॉन्क्लेव में सरकार, उद्योग, शिक्षा, नीति-निर्माता और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारकों को युवाओं के आर्थिक समावेशन और सशक्तीकरण के लिए नीतियां बनाने के उद्देश्य से एक मंच पर लाया गया।

कौशल साथी

कौशल साथी पहल के तहत एनवाईसीएस अखिल भारतीय स्तर पर मानकों के साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट और कुशल परामर्श के माध्यम से अभ्यर्थियों को परामर्श देती है, ताकि कौशल द्वारा रोजगार योग्यता को बढ़ाया जा सके।

गेल इंडियन स्पीडस्टार

एनवाईसीएस ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में 11 से 17 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं के लिए एक अनूठा अखिल भारतीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम 'गेल रफ्तार इंडियन स्पीडस्टार' का वर्ष 2016 से 2019 तक सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की खोज, चयन, पोषण और संवर्धन करना तथा उन्हें एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने के लिए प्रशिक्षित करना था। इस प्रतिभा खोज कार्यक्रम में गांव, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 4,50,000 से अधिक खेल प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इंडिया का खेलोत्सव

इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की। इंडिया का खेलोत्सव स्पोर्ट्स एक्सपो में खेल प्रशासकों को सम्मानित किया गया। एनवाईसीएस एथलीटों को चैंपियन बनाने के लिए मजबूत समर्थन देती है। खेलोत्सव में एनवाईसीएस के एथलीट निसार अहमद ने अंडर-17 की 100 मीटर स्पर्धा में 10.96 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। पी डिनिनल ने 800 मीटर में स्वर्ण और ताई बाम्हने ने 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता।

जन औषधि केंद्र

किफायती दवाओं के स्टोर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने में एनवाईसीएस रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एजेंसी बीपीपीआई (भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो) का एक कार्यान्वयन भागीदार है। एनवाईसीएस 7 राज्यों में 22 जन औषधि केंद्र खोलने में सफल रही है।

उज्ज्वला दीदी

सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ साझेदारी में ओडिशा में एनवाईसीएस की यह एक और सफल पहल थी। इस कार्यक्रम के तहत संगठन ने ओडिशा के सभी 30 जिलों और 450 ब्लॉकों में 6 महीने की अवधि में 10 हजर जमीनी ऊर्जा उद्यमियों को प्रशिक्षित किया।

युवा मंथन

2018 में आयोजित यह दो दिवसीय कार्यक्रम नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए विकासात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने हेतु एक साझा मंच था।

युवा एक्सपो

युवा एक्सपो एनवाईसीएस का एक इवेंट मैनेजमेंट डिवीजन है। इसने 2006 में नई दिल्ली, 2008 में रायपुर, 2011 में नई दिल्ली और 2013 में भोपाल में युवा को-ऑप एक्सपो का आयोजन किया था। इस एक्सपो में प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया और युवा सशक्तीकरण पर अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए, जिससे प्रतिनिधियों को भारत में उद्यमिता और देश के आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में प्रोत्साहन मिला।

ग्रामीण होमस्टे परियोजना

बैक टू विलेज (बी2वी) के सहयोग से एनवाईसीएस मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा के 4 आदिवासी गांवों में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण होमस्टे परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक गांव में कम से कम 10 होमस्टे बनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसके तहत विभिन्न सामूहिक गतिविधियों (ग्रामीण खेल, लोक नृत्य, लोक संगीत, नाटक, भजन आदि) पर भी काम किया जा रहा है।

युवाओं की सहकारिता में सहभागिता के जरिये विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विकसित भारत बनाने में एक तरफ कॉरपोरेट की और दूसरी ओर कोऑपरेटिव की भूमिका होगी।

इन युवाओं की सहकारिता में सहभागिता के जरिये विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विकसित भारत बनाने में एक तरफ कॉरपोरेट की और दूसरी ओर कोऑपरेटिव की भूमिका होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें एनवाईसीएस का क्या योगदान होगा, अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन में इस पर भी मंथन किया जाएगा। एनवाईसीएस अब 25 वर्ष का हो चुका है और अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। पहली बार यह संस्था मुनाफे में आई है। अब हमारा समय आ गया है कि हम कुछ करके दिखाएं।'

एनवाईसीएस ने पिछले तीन-चार वर्षों में जननिधि पर फोकस किया है। करीब 60 हजार से ज्यादा लोगों को लोन के माध्यम से, रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाया गया है और उन्हें उनकी आजीविका के लिए तैयार किया है। हालांकि, सहकारिता क्षेत्र में जननिधि का योगदान अभी बहुत छोटा है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले तीन-चार वर्षों में एनवाईसीएस का कारोबार 500 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए। एनवाईसीएस का टर्नओवर 2024-25 में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और उनके उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एनवाईसीएस जननिधि नाम से एक माइक्रो फाइनेंस डिवीजन चलाता है। वर्तमान में देश भर के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जननिधि के 35 केंद्र संचालित हैं। इसके माध्यम से 40,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

बड़ा सोचने और हकीकत में बदलने की ओर कदम

इसी तरह, मध्य प्रदेश में एनवाईसीएस और बैक टू विलेज (बी2वी) के सहयोग से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाला प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत ग्रमीणों को होम स्टे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को गांव में ही स्वरोजगार के लिए मदद मुहैया

सहकारिता एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है जो भारत के व्यापक विकास का सपना पूर्ण कर सकता है। इसमें विकसित भारत का आधार बनने की क्षमता है।

कराई जाती है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से संचालित यह कार्यक्रम भले ही अभी संगठन की ओर से छोटे स्तर पर संचालित किया जा रहा है लेकिन यह काफी सफल रहा है। राज्य के चार जिलों में एनवाईसीएस और बी2वी इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है जिसकी जिम्मेदारी बी2वी के संस्थापक और एनवाईसीएस के उपाध्यक्ष मनीष कुमार के कंधों पर है। मनीष आईआईटी ग्रेजुएट हैं। ग्रामीणों और युवाओं की उन्नति और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की उनकी सोच ही उन्हें कॉरपोरेट की जगह कोऑपरेटिव की ओर खींच लाई। मध्य प्रदेश की सफलता से उत्साहित होकर एनवाईसीएस भविष्य में इसे अन्य राज्यों में भी शुरू करने की योजना बना रहा है। राजेश पांडे ने कहा, 'हालांकि यह बहुत धैर्य का काम है लेकिन अगर इसके माध्यम से गांव में ही लोगों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध होता है तो विकसित भारत बनाने में इसका भी बड़ा योगदान होगा। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि नए-नए क्षेत्रों से जुड़ें और यह कोशिश करें कि संगठन और आगे बढ़े। नवंबर में जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वह इसी सोच का परिणाम है। संगठन अब बड़े स्तर पर सोचने और उसे पूरा करने के प्रयास में जुटा है। भारत अगले दो दशक तक युवा रहने वाला है और हमारे पास मौका है कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों और युवाओं को अपने साथ जोड़ें। हम अब इसी मिशन मोड में काम करने वाले हैं जिसकी शुरुआत नवंबर से होने वाली है।'

सहकारिता से ही होगा

एनवाईसीएस के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए राजेश पांड ने कहा कि जिला और राज्य प्रतिनिधि सहकारिता से जुड़ी छोटी-छोटी गतिविधियां करते रहें ताकि सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिले और इस आंदोलन में संगठन की भागीदारी दिखती रहे। व्यक्तिगत तौर पर हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। हम सबको अपनी-अपनी ओर से पहल करनी चाहिए तभी सहकारिता मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री का यही मिशन है कि देश का विकास सहकारिता के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए उनका पूरा फोकस सहकारिता को मजबूती देने पर है। सहकारिता मजबूत होगी तो देश के विकास में इस क्षेत्र का योगदान ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए हम सबको पहल करनी होगी। सहकारिता में इतनी क्षमता है कि इसके माध्यम से कुछ भी संभव किया जा सकता है, बशर्ते जरूरत है सभी की सहभागिता और सही मार्गदर्शन की। जो इस क्षेत्र में सक्रिय रहेगा वही आगे बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में एनवाईसीएस का चुनाव होगा। तब एक नई टीम बनेगी जो संगठन को और आगे ले जाएगी। एक अच्छी टीम ही संगठन को बेहतर कल की ओर ले जा सकती है। हमारे वरिष्ठों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसे पूरा करना ही हमारा सपना है।■

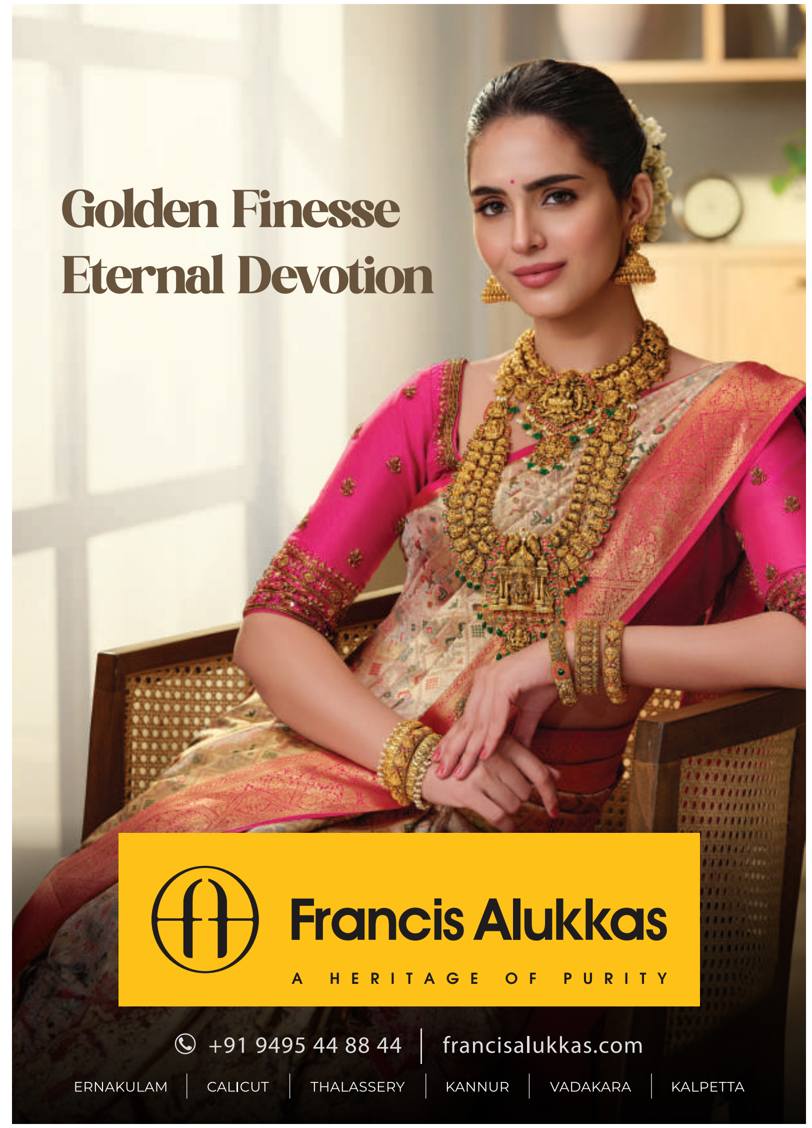

अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन नवंबर में

एनवाईसीएस और पीडब्ल्यूआईएफ के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित होगा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

युवा सहकार टीम

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) नवंबर 2025 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन का विषय 'युवा सहकारः विकसित भारत का आधार' रखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह की उपस्थिति में 22 अगस्त को नई दिल्ली स्थित एनसीयूआई सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन 2025 की विवरणिका विमोचन भी किया गया। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन (पीडब्ल्यूआईएफ) के सहयोग से इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा।

> **एनवाईसीएस अपनी स्थापना के बाद से ही युवाओं का कौशल विकास करने और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। एनवाईसीएस स्वरोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती है।**

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवप्रकाश ने अपने संबोधन में एनवाईसीएस के इस प्रयोजन की सराहना करते हुए कहा, 'भारत सहकारिता के माध्यम से देश को विकसित बनाने के लिए क्या-क्या कर रहा है, इस सम्मेलन के जरिये दुनिया को संदेश दिया जाएगा। एनवाईसीएस अपनी स्थापना के बाद से ही युवाओं का कौशल विकास करने और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। एनवाईसीएस स्वरोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती है। सहकारिता के मॉडल में ही सबकी आर्थिक उन्नति की क्षमता है।'

दिल्ली प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली के कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी। साथ ही, यह भी प्रयास किया जाएगा कि रेहड़ी-पटरी वालों को कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से कैसे कम ब्याज पर आसान कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एनवाईसीएस की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन राजेश पांडे ने युवाओं की इस सहकारी संस्था की 25 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'एनवाईसीएस का देशभर में फैला नेटवर्क ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। देश के विकास में सहकारिता के माध्यम से युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को ध्यान में रखकर ही अंतरराष्ट्रीय युवा सहकार सम्मेलन का थीम 'युवा सहकारः विकसित भारत का आधार' रखा गया है। युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल देश के विकास में कैसे किया जाए और उनका योगदान कैसे बढ़ाया, इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस पर चर्चा की जाएगी।' कार्यक्रम में एनवाईसीएस के प्रेसीडेंट प्रकाश चंद्र साहू ने संगठन की स्थापना के उद्देश्य और उपलब्धियों के बारे में बताया है।

इस कार्यक्रम में सहकार भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर, पुरुलिया के सांसद और एनवाईसीएस के डायरेक्टर ज्योतिर्मय महतो, एनवाईसीएस के एमडी एवं सीईओ रविंद्र कुलकर्णी सहित संगठन के देशभर से आए प्रतिनिधि उपस्थिति थे। इस एक दिवसीय सम्मेलन में पांच सत्र आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन सत्र का विषय 'युवा सहकारः विकसित भारत का आधार' रखा गया है। जबकि अन्य सत्रों के विषय में 'अब बदल रहा है विकास का पैमाना' 'युवा शक्ति बनेगी सहकारिता का आधार', 'पेशेवर उत्कृषटता के लिए कौशल विकास का महत्व' और 'सहकारिता की पढ़ाईः विकास का नया मॉडल' शामिल हैं।■

> **युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल देश के विकास में कैसे किया जाए और उनका योगदान कैसे बढ़ाया, इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस पर चर्चा की जाएगी।**

एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में एनवाईसीएस की रही मजबूत भागीदारी

युवा सहकार टीम

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के युवाओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। यह संवाद युवा नेताओं को नए समाधान साझा करने और नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य हरित परिवर्तन, डिजिटल समावेशन और महामारी के बाद की रिकवरी में विकास ढांचों और नीतिगत परिणामों को प्रभावित करना था। 12-13 अगस्त को संपन्न हुआ यह दो दिवसीय सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। आईसीए-एशिया पेसिफिक यूथ कोऑपरेशन कमिटी (आईसीवाईसी) और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान (यूएनआरआईएसडी) के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था। भारत की ओर से इस सम्मेलन में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की।

> **12-13 अगस्त को संपन्न हुआ यह दो दिवसीय सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। आईसीए-एशिया पेसिफिक यूथ कोऑपरेशन कमिटी (आईसीवाईसी) और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान (यूएनआरआईएसडी) के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था।**

यह संवाद पांच विषयों पर केंद्रित था जिनमें जलवायु कार्रवाई और स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सामाजिक-आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य और कल्याण, युवा नवाचार, शांति और सीमा पार सहयोग शामिल था। एनवाईसीएस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए एनवाईसीएस के महाप्रबंधक अभिषेक कुमार ने कहा, 'एनवाईसीएस एक अद्वितीय युवा नेतृत्व वाला संगठन है जो सहकारी मूल्यों, नवाचार और राष्ट्रीय विकास पहलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा सशक्तीकरण राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। एनवाईसीएस ने भारत में युवा कौशल विकास, सहकारी उद्यमिता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाली कई पहलों पर काम किया है।'

युवा नवाचार, शांति और सीमा पार सहयोग विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे लिए शांति का अर्थ न्याय, समझ और सामाजिक एकजुटता की सक्रिय उपस्थिति है, न कि केवल संघर्ष का अभाव। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी के साथ अपने पेशेवर सफर में मैंने भारत में हजारों युवाओं के साथ काम किया है, जिनमें से कई संघर्षग्रस्त, आर्थिक रूप से वंचित या सामाजिक रूप से बिखरे क्षेत्रों से हैं। मैंने जो सीखा है वह यह है कि युवा केवल शांति की इच्छा नहीं रखते, हम इसे जमीन से ऊपर उठाने में सक्षम हैं। शिक्षा निःसंदेह शांति के सबसे मजबूत साधनों में से एक है। यह गरीबी और पूर्वाग्रह के चक्र को तोड़ती है और युवा मन को सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच और संवाद की शक्ति खोजने में मदद करती है। इस संवाद सम्मेलन में मेरी आवाज उन युवाओं के लिए है जो वास्तविक दुनिया के संघर्षों का सामना करते हुए सम्मान, अवसर और सद्भाव के लिए प्रयास करते हैं। मैं उन अनगिनत युवाओं के लिए भी बोल रहा हूं जो कक्षाओं, सहकारी समितियों और समुदायों में अपने-अपने तरीके से शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। आज शांति समावेशी, जमीनी स्तर पर संचालित और युवाओं के नेतृत्व वाली होनी चाहिए। मैं उस दृष्टिकोण को जीवंत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। संवाद, सहयोग और कार्रवाई के माध्यम से मैं न केवल राष्ट्रों के भीतर, बल्कि पूरी मानवता के लिए स्थायी शांति के निर्माण में सार्थक योगदान देने को लेकर आशावान हूं।'

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की 60 प्रतिशत से ज्यादा युवा आबादी रहती है, जो युवाओं को नवाचार, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए आवश्यक प्रेरक बनाती है। चूंकि यह क्षेत्र गंभीर सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए ऐसे समावेशी मंच बनाने की जरूरत बढ़ रही है जहां युवा सार्थक संवाद में शामिल हो सकें और ऐसी नीतियों को आकार देने में योगदान दे सकें जो उनके भविष्य को सीधे प्रभावित करे।

इस जरूरत को देखते हुए ही आईसीवाईसी और यूएनआरआईएसडी एशिया-प्रशांत में युवाओं पर क्षेत्रीय संवाद का सह-आयोजन करने के लिए एक साथ आए। अंतरराष्ट्रीय मंच वी द यूथ (आईएफडब्ल्यूवाई) के साथ की गई इस पहल का उद्देश्य युवाओं की आवाज को बुलंद करना और सहकारी कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, डिजिटल नवाचार और सामाजिक समानता पर केंद्रित संरचित, आकर्षक बातचीत के माध्यम से युवा नेताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच की खाई को पाटना था।

अभिषेक कुमार ने 'युवा सहकार' को बताया कि मैं अंतरराष्ट्रीय मंच वी द यूथ (आईएफडब्ल्यूवाई) में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे युवा नेताओं के एक वैश्विक संगम के रूप में देखता हूं जो अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थायी भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ऐसे मंचों की वकालत करता हूं जहां युवाओं की आवाजें नीति, संवाद और विकास के केंद्र में हों। मेरा मानना है कि आईएफडब्ल्यूवाई मेरे काम को आगे बढ़ा सकता है और वैश्विक और स्थानीय स्तर पर युवाओं के नेतृत्व वाले बदलाव के उद्देश्य को मजबूत कर सकता है।

इस क्षेत्रीय संवाद से ठोस और प्रभावशाली परिणाम निकले जो शासन, विकास और सहकारी आंदोलनों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में योगदान देंगे। यह आयोजन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में युवा नेटवर्क को मजबूत करने में भी मददगार रहा जिससे सहकारी समितियों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को नीति को प्रभावित करने और क्षेत्रीय पहलों पर सहयोग करने के अवसर प्रदान करके वैश्विक निर्णय लेने वाले मंचों में युवाओं के दृष्टिकोण को बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामूहिक प्रयास, सार्थक संवाद और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से यह पहल न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनकी आवाज एक अधिक समावेशी और सहयोगात्मक भविष्य के लिए वास्तविक दुनिया के समाधानों को प्रेरित करे।■

> **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की 60 प्रतिशत से ज्यादा युवा आबादी रहती है, जो युवाओं को नवाचार, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए आवश्यक प्रेरक बनाती है। चूंकि यह क्षेत्र गंभीर सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए ऐसे समावेशी मंच बनाने की जरूरत बढ़ रही है जहां युवा सार्थक संवाद में शामिल हो सकें और ऐसी नीतियों को आकार देने में योगदान दे सकें जो उनके भविष्य को सीधे प्रभावित करे।**

टैक्स सुधार

जीएसटी कटौती से सहकारी संस्थाएं होंगी मजबूत

सहकारी संस्थाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों सहित 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को होगा सीधा लाभ

ट्रैक्टरों एवं कृषि उपकरणों सहित फर्टिलाइजर क्षेत्र के लिए किए गए उपायों से घटेगी खेती की लागत

युवा सहकार टीम

ट्रंप टैरिफ से मुश्किल में घिरी भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में व्यापक सुधार किया है। इसकी बदौलत घरेलू खर्च में कमी आएगी और मांग बढ़ेगी। घरेलू मांग बढ़ेगी तो कल-कारखानों के पहिए तेज रफ्तार से घूमेंगे जिससे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। जीसटी में बड़ी कटौती से सहकारी संस्थाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों सहित 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को भी सीधा लाभ होगा। ये सुधार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे, उनके उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, उनके उत्पादों की मांग और उनकी आय बढ़ाएंगे। यह ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारिताओं को प्रोत्साहित करेगा और लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुएं किफायती रूप से उपलब्ध कराएगा।

सरकार ने जीएसटी की चार दरों (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) को घटाकर सिर्फ दो (5 और 18 प्रतिशत) करने का फैसला किया है। साथ ही 28 प्रतिशत वाले स्लैब पर लगने वाला सेस भी हटा दिया है। इसकी जगह टैक्स की नई दर 40 प्रतिशत को लागू करने का फैसला किया गया है जो लग्जरी वस्तुओं के लिए है। हालांकि, यह दर 28 प्रतिशत के मुकाबले काफी ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद लग्जरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि पहले इन पर 22 प्रतिशत तक सेस लगता था जिसकी वजह से इन पर कुल टैक्स का भार 50 प्रतिशत तक हो जाता था। मगर अब यह 40 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमोबाइल और कन्ज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। जीएसटी की नई दर 22 सितंबर से लागू करने की घोषणा सरकार ने की है।

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगा लाभ

जीएसटी दर में कटौती खेती और पशुपालन में लगी सहकारिताओं को लाभ पहुंचाएगी, टिकाऊ खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देगी और छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सीधा फायदा देगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताओं को काफी मजबूती मिलेगी। दुग्ध क्षेत्र को जीएसटी में सीधे राहत दी गई है। दूध और पनीर को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जबकि मक्खन, घी और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तरों पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे दुग्ध उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, दुग्ध किसानों को सीधी राहत मिलेगी, विशेषकर दुग्ध प्रसंस्करण में लगी महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ेगी जिससे उन्हें मजबूती मिलेगी। इसी तरह, चीज, नमकीन, मक्खन और पास्ता पर जीएसटी 12 या 18 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जैम, जेली, खमीर, भुजिया और फलों का गूदा, जूस आधारित पेय पदार्थ अब 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और कॉफी पर भी जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। कम जीएसटी से खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च घटेगा जिससे मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताएं तथा निजी डेयरियां मजबूत होंगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

इससे करोड़ों किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सालाना 11,400 करोड़ रुपये की बचत होगी। देश की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव अमूल के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा, 'इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इस कटौती के बाद अमूल का आधा कारोबार शून्य प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में आएगा, जबकि शेष पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जीएसटी में बदलाव से किसानों की आय में सुधार होगा और मांग में भी वृद्धि होगी।' इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और अमूल के पूर्व प्रबंध निदेशक आर. एस. सोढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, 'सभी प्रमुख डेयरी उत्पादों पर जीएसटी कम करने से लगभग 8 करोड़ किसानों और 145 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे सालाना 11,400 करोड़ रुपये की बचत होगी।'

डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम करने के जीएसटी काउंसिल के फैसले की सराहना करते हुए मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा, 'यह प्रगतिशील कदम देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। भारतीय घरों में तेजी से लोकप्रिय हो रही पैकेज्ड श्रेणी के लिए यह विशेष रूप से बढ़ावा है। आगे चलकर इनकी मांग में और तेजी आएगी। यह किसानों के लिए बेहतर बाजार अवसर पैदा करेगा और समग्र रूप से डेयरी उद्योग को और ऊर्जा प्रदान करेगा।'■

दुग्ध क्षेत्र को जीएसटी में सीधे राहत दी गई है। दूध और पनीर को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जबकि मक्खन, घी और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

खेती-किसानी की घटेगी लागत

जीएसटी काउंसिल ने खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर टैक्स की दरों में कटौती का जो फैसला किया है, उससे किसानों को 1.87 लाख रुपये तक की बचत होगी। इन उपकरणों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। इनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, धान ट्रांसप्लांटर, थ्रेशर, पावर वीडर, ट्रेलर, बीज-खाद देने वाले ड्रिल, हार्वेस्टर कंबाइन, सुपर सीडर, हैपी सीडर, रोटोवेटर आदि शामिल हैं। इसका लाभ केवल फसल उत्पादक किसानों को ही नहीं, बल्कि पशुपालन और मिश्रित खेती करने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि इनका उपयोग चारे की खेती, चारे के परिवहन और कृषि उत्पाद प्रबंधन में भी किया जाता है। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप सहित अन्य कलपुर्जों पर भी जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

फर्टिलाइजर क्षेत्र में अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 कर दिया गया है। इससे फर्टिलाइजर कंपनियों की इनपुट लागत घटेगी, किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी और बुवाई के समय पर किफायती फर्टिलाइजर उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार, 12 बायो-पेस्टीसाइड और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जैव-आधारित कृषि इनपुट अधिक किफायती होंगे, किसान रासायनिक कीटनाशकों से हटकर बायो-पेस्टीसाइड की ओर बढ़ेंगे, मिट्टी की सेहत और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी और छोटे जैविक किसानों तथा एफपीओ को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन के अनुरूप है।

एनसीडीसी के प्रोत्साहन से मजबूत हो रही कोऑपरेटिव्स

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में सहकारी समितियों को 95 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का दिया वित्तीय प्रोत्साहन

मार्केटिंग क्षेत्र की कोऑपरेटिव सोसाइटियों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए मिले 77,942.72 करोड़ रुपये

एनसीडीसी के कदम से राज्यों और सहकारी संस्थाओं को कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए मजबूती मिली

चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 जून तक तीन महीने में ही एनसीडीसी ने 26,425.75 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कर दिए हैं। इस दौरान फसलों की खरीद के लिए 25,984.83 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे सहकारी संस्थाओं को न सिर्फ अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिल रही है, बल्कि ये संस्थाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं।

युवा सहकार टीम

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से भारत को विकसित देश बनाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने में एनसीडीसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनसीडीसी देश भर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद पहुंचाती है। इसके माध्यम से सहकारिता की निचली इकाई पैक्स से लेकर शीर्ष इकाई अपेक्स तक को भरपूर वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2023 में एनसीडीसी को तीन वर्ष में सहकारिता क्षेत्र को सालाना एक लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का लक्ष्य दिया था जिसे समय से पहले ही लगभग पूरा कर लिया गया है।

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब के मुताबिक एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 में सहकारी संस्थाओं को 95,182.84 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है। इनमें सबसे ज्यादा 77,942.72 करोड़ रुपये की मदद मार्केटिंग क्षेत्र में सक्रिय कोऑपरेटिव सोसायटियों को दी गई है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटियों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी उपज की खरीद के लिए एनसीडीसी द्वारा ये आर्थिक सहायता दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 जून तक तीन महीने में ही एनसीडीसी ने 26,425.75 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कर दिए हैं। इस दौरान फसलों की खरीद के लिए 25,984.83 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे सहकारी संस्थाओं को न सिर्फ अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिल रही है, बल्कि ये संस्थाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं।

पिछला लक्ष्य हासिल होने के साथ ही एनसीडीसी ने अब अगले पांच वर्षों के लिए नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत वित्तीय सहायता को 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इस रणनीति के केंद्र में वह सहकारी समितियां हैं जो अब तक हाशिए पर रही हैं-जैसे मत्स्य पालन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहाड़ी समितियां, हथकरघा, डेयरी, कुक्कुट पालन और महिला श्रमिक समितियां। यह कदम सहकारिता क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी अहम होगी। एनसीडीसी ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में कुल 1,621 ऋण स्वीकृत और वितरित किए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 2,31,053.79 करोड़ रुपये है। किसानों की माली हालत में सुधार को प्रतिबद्ध सहकारिता मंत्रालय कृषि ऋण की सहकारिताओं को उच्च प्राथमिकता देता है। देश की 8 लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को एनसीडीसी से ही रियायती दरों पर ऋण प्राप्त होता है।

एनसीडीसी के इस कदम से राज्यों और सहकारी संस्थाओं को कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए मजबूती मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास से देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती मिल रही है। रोजगार के साधन बढ़े हैं। सुनिश्चित खाद्यान्न आपूर्ति से महंगाई पर पर काबू पाने में मदद मिली है। किसानों की उपज की खरीद, भंडारण और वितरण क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मिली सहूलियत से उनके कारोबार में वृद्धि हुई है।

2,31,053.79	करोड़ रुपए चार वित्त वर्ष में सहकारी समितियों को मिले
2,00,000	करोड़ रुपए सालाना प्रोत्साहन का रखा गया है नया लक्ष्य
1,00,000	करोड़ रुपए सालाना देने का लक्ष्य समय से पहले हुआ पूरा

सहकारिता क्षेत्र की लघु से लेकर वृहद संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी नजर उन 60 करोड़ लोगों पर है जो पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। उनकी नजर उन गरीब और कम आय वर्ग के लोगों पर है जो पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर देश के गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा आवंटन

एनसीडीसी से ऋण प्राप्त करने में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब की सहकारी संस्थाएं अव्वल रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी ने 535 ऋण वितरित किए, जिनकी कुल राशि 95,182.84 करोड़ रुपये है। इस दौरान एनसीडीसी के प्रमुख लाभार्थी राज्यों में छत्तीसगढ़ नंबर एक पर रहा है जहां की सहकारी संस्थाओं को 28,080 करोड़ रुपये

एनसीडीसी ने अब अगले पांच वर्षों के लिए नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत वित्तीय सहायता को 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इस रणनीति के केंद्र में वह सहकारी समितियां हैं जो अब तक हाशिए पर रही हैं झ जैसे मत्स्य पालन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहाड़ी समितियां, हथकरघा, डेयरी, कुक्कुट पालन और महिला श्रमिक समितियां।

आर्थिक सशक्तीकरण

केंद्रीय अनुदान सहायता

सहकारी समितियों की नई परियोजनाओं को स्थापित करने, उनके संयंत्रों का विस्तार करने और उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीडीसी को केंद्रीय अनुदान सहायता योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक की इस योजना के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में एनसीडीसी को 500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी जाएगी। इस अनुदान सहायता के आधार पर एनसीडीसी चार वर्ष की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगी, जिसका उपयोग सहकारी समितियों की वित्तीय सहायता के रूप में की जाएगी। इसके माध्यम से देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियां और श्रमिकों एवं महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लगभग 2.90 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता से सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी। इससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कृषि विपणन एवं निवेश, प्रसंस्करण और भंडारण क्षेत्रों को सहायता देने और देश में युवाओं की आय को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाने से एनसीडासी का दायरा व्यापक हो गया है। निर्यात, जैविक और बीज उत्पादन पर गठित तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी एनसीडीसी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वितरित किए गए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर रहे तेलंगाना को 20,980.07 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश में 16,330 करोड़ रुपये और पंजाब की सहकारी समितियों को 5,702 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है। इनके अलावा नैफेड और एनसीसीएफ जैसी राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता मिली है। इस वित्त वर्ष में नैफेड को 97 करोड़ रुपये और एनसीसीएफ को 1,119.36 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

कोऑपरेटिव बैंकों को मिले 42,000 करोड़ रुपये

संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई एक जानकारी में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंकों को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की। एनसीडीसी की ओर से इस अवधि में आंध्र प्रदेश (3,730 करोड़ रुपये) और तेलंगाना (2,000 करोड़ रुपये) के कोऑपरेटिव बैंकों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद दी गई, जबकि मध्य प्रदेश (291 करोड़ रुपये) और राजस्थान (77 करोड़ रुपये) को भी वित्तीय सहयोग मिला। इसी तरह, नाबार्ड के वितरण में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 4,430 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बाद ओडिशा (4,113 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (3,655.52 करोड़ रुपये) को लाभ मिला। 31 मार्च, 2025 तक देश में 34 राज्य सहकारी बैंक, 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 1,457 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत थे। वित्तीय प्रवाह और डिजिटल एकीकरण के साथ सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा।

एनसीडीसी का बढ़ता दायरा

सहकारिता क्षेत्र के विकास में मदद करने में एनसीडीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है। एनसीडीसी सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसने अपना दायरा बढ़ाया है। कृषि विपणन एवं निवेश, प्रसंस्करण और भंडारण क्षेत्रों को सहायता देने और देश में युवाओं की आय को बढ़ावा देने के लिए सार्थक कदम उठाने से एनसीडासी का दायरा व्यापक हो गया है। निर्यात, जैविक और बीज उत्पादन पर गठित तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी एनसीडीसी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

अन्न भंडारण योजना

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी समितियों के विकास के लिए 100 से अधिक पहलें हुई हैं। केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना शुरू की है, जिस पर एक लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। गोदामों का निर्माण करने, खाद्यान्न का भंडारण, विपणन और प्रसंस्करण का दायित्व प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को सौंपा गया है। इसके तहत 7 करोड़ टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति की देखरेख में यह योजना काम कर रही है, जिसका बड़ा दायित्व एनसीडीसी को सौंपा गया है। एनसीडीसी ही इस योजना को वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है।

सहकारी चीनी मिलों को बड़ा पैकेज

सहकारिता मंत्रालय एनसीडीसी के माध्यम से चीनी उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। वर्ष 1950 में जहां सहकारी क्षेत्र में केवल दो चीनी मिलें थी वह आज बढ़कर 312 तक पहुंच गई हैं। देश के कुल चीनी उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना, पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण और पेराई क्षमता के विस्तार के लिए सहायता दी जाती है। चीनी निर्यात में भी सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सहकारिता मंत्रालय का पूरा जोर चीनी उत्पादन के साथ एथनॉल उत्पादन पर है। सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल संयंत्र, सह उत्पादन संयंत्र की स्थापना और कार्यशील पूंजी के लिए एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 48 मिलों को 9,893.12 करोड़ रुपये के 87 लोन स्वीकृत किए हैं। 2024-25 में इन्हें 7,975.54 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

डेयरी और मत्स्य पालन

सहकारिता मंत्रालय के फोकस एरिया में लघु व सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसान भी हैं। इसीलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर एनसीडीसी द्वारा वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। डेयरी क्षेत्र की सहकारी समितियों को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी डेयरी सहकार नाम से एक योजना चलाती है। इस योजना का मकसद सहकारी समितियों के आधारभूत ढांचे का निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार में मदद करना है। इसके लिए सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण, ऋण गारंटी और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि डेयरी और पशुधन से जुड़ी सहकारी समितियों को एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 1765.11 करोड़ रुपये की वित्तीय दी है। इसी तरह मत्स्य सहकारी समितियों को इस दौरान 818.24 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है।

एनसीडीसी मत्स्य सहकारी समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन आदि से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता प्रदान करता है। इन गतिविधियों में मछली पकड़ने वाली नावों, जालों और इंजनों जैसे परिचालन इनपुट की खरीद करने के अलावा विपणन, परिवहन वाहनों, बर्फ संयंत्रों, शीतगृहों, खुदरा दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है। साथ ही अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल संवर्धन, बीज फार्म, हैचरी आदि का विकास, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, एकीकृत मत्स्य पालन परियोजनाएं (समुद्री, अंतर्देशीय और खारे पानी) और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज की खरीद के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। ■

कुल वित्तीय प्रोत्साहन और प्रमुख लाभार्थी राज्य

वित्त वर्ष	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	95,182.84	60,618.47	41,031.40	34,221.08
छत्तीसगढ	28,080	18,990	8,500	12,400
आंध्र प्रदेश	20,980.07	13,269.90	9,686.19	--
तेलंगाना	16,330	11,930.99	9,091.26	9,906.57
पंजाब	5,702	--	--	--
हरियाणा	--	--	--	12,824.83

सहकारिता मंत्रालय के फोकस एरिया में लघु व सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसान भी हैं। इसीलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर एनसीडीसी द्वारा वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है।

ट्रम्प टैरिफ से रोजगार पर संकट

युवा सहकार टीम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सख्त टैरिफ नीतियों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। इससे न सिर्फ उन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, बल्कि इससे नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। भारत पर इसकी ज्यादा मार पड़ने की आशंका है क्योंकि रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करने के कारण ट्रम्प ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और अपने कुल निर्यात का 18 प्रतिशत अमेरिका को निर्यात करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी करीब 2 प्रतिशत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिकी निर्यात में गिरावट आती है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था 1-2 प्रतिशत तक घट सकती है।

भारी भरकम टैरिफ होने से अमेरिका में भारतीय सामानों की कीमत बढ़ गई है जिससे इनकी मांग आने वाले दिनों में घटने की पूरी संभावना है। मांग घटेगी तो उत्पादन कम होगा और उत्पादन घटेगा तो रोजगार पर संकट आएगा। अमेरिकी टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है और इसका असर भी दिखने लगा है, लेकिन सही आंकड़ा अगले दो-तीन महीनों में ही मिल पाएगा कि इससे कितना नुकसान हो रहा है और रोजगार पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। हालांकि निर्यात संगठनों का अनुमान है कि इस टैरिफ से अमेरिका को होने वाला 55-60 प्रतिशत निर्यात प्रभावित हो सकता है। अनुमान जताया जा रहा है कि इससे लाखों रोजगार पर संकट आएगा। खासकर कपड़ा और परिधान, गहने एवं रत्न, ऑटो कंपोनेंट्स, झींगा एवं समुद्री उत्पाद और केमिकल एवं ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े रोजगार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन्हीं पांच क्षेत्रों से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होता है। दिक्कत निर्यात में कमी तो है ही, साथ ही अमेरिकी बाजार में भारतीय हिस्सेदारी के प्रतिस्पर्धी देशों के हाथों में जाने की भी है। बांग्लादेश, वियतनाम समेत कई देशों पर अमेरिकी टैरिफ की दर भारत के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में इन देशों के उत्पाद भारतीय सामान की तुलना में अमेरिकी बाजार में अधिक सस्ते हो गए हैं। इसका असर भारतीय निर्यात के भविष्य पर होगा। अमेरिका ने पहले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल आयात करने के खिलाफ कदम उठाने की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने 25 प्रतिशत की पेनाल्टी लगा दी जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया।

भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ से घटेगा निर्यात, अमेरिका को होता है सबसे ज्यादा 18 प्रतिशत निर्यात

7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के भारतीय उत्पादों का अमेरिका को होता है निर्यात

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका का व्यापार 131.8 अरब डॉलर रहा है। इसमें से भारत ने 86.5 अरब डॉलर का निर्यात (रुपये में कीमत 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) और 45.3 अरब डॉलर का आयात किया है यानी भारत का सरप्लस 41.2 अरब डॉलर रहा है जो अमेरिका का व्यापार घाटा है। अमेरिका इसी व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। उसका कहना है कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है जिसकी वजह से उसके उत्पादों की कीमत भारत में बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से अमेरिकी उत्पादों का निर्यात भारत को नहीं हो पाता है। जबकि भारत का कहना है कि स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ही विदेशी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। भारत के पांच सेक्टर से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होता है और इन पांच सेक्टर पर ही टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

कपड़े और परिधान

अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद कपड़ा और परिधान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में हैं। तैयार कपड़ों पर टैरिफ करीब 64 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र के करीब 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निर्यात पर असर पड़ेगा। भारतीय कपड़ा उद्योग में 4.5 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हथकरघा श्रमिक शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी कार्यरत हैं। एक अनुमान के अनुसार, अमेरिका को निर्यात करने वाली कपड़ा इकाइयों में करीब 15 लाख लोग कार्यरत हैं। निर्यात प्रभावित होने से इन लोगों के रोजगार पर सीधा संकट खड़ा होना तय है।

गहने और रत्न

अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के गहनों और रत्नों के उद्योग को भी बड़ा झटका लग सकता है। अनुमान है कि इस क्षेत्र का करीब 85 हजार करोड़ रुपये का निर्यात प्रभावित होगा। कटे हुए हीरों का भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। सूरत और मुंबई जैसे शहरों में लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। नया टैरिफ भारतीय डायमंड इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर सकता है।

ऑटो कंपोनेंट्स

भारत अमेरिका को हर साल करीब 58 हजार करोड़ रुपये के ऑटो कंपोनेंट्स निर्यात करता है। 50 प्रतिशत टैरिफ लगने से इस क्षेत्र को भी बड़ा झटका लग सकता है। निर्यात में गिरावट आने से यहां भी रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में जो कटौती की है उसका सबसे ज्यादा फायदा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही मिलता दिख रहा है। कारों पर जीएसटी की दर घटने और सेस खत्म होने से कारें 40 हजार रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं जिससे घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है। त्योहारी मौसम शुरू हो गया है और इस दौरान घरेलू बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हो सकता है कि इस सेक्टर पर टैरिफ का असर हाल फिलहाल कम दिखे।

झींगा और समुद्री खाद्य पदार्थ

भारत अमेरिका को छह अरब डॉलर से अधिक के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। इसमें सबसे अधिक निर्यात झींगा का है। इसके अलावा बासमती चावल, मसाले, फल-सब्जियां और ऑयल एसेंस जैसे कृषि उत्पादन कृषि निर्यात का प्रमुख हिस्सा हैं। 50 प्रतिशत टैरिफ लगने से इस निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है। सबसे बुरा असर तेजी से बढ़ रहे झींगा उद्योग पर पड़ेगा क्योंकि इस शुल्क के बाद यह प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएगा। भारत दुनिया के शीर्ष झींगा निर्यातकों में शामिल है। भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले झींगा और दूसरे समुद्री उत्पादों का लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे पूर्वी तटीय राज्यों में लाखों लोगों को रोजगार देता है।■

अनुमान जताया जा रहा है कि इससे लाखों रोजगार पर संकट आएगा। खासकर कपड़ा और परिधान, गहने एवं रत्न, ऑटो कंपोनेंट्स, झींगा एवं समुद्री उत्पाद और केमिकल एवं ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े रोजगार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन्हीं पांच क्षेत्रों से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होता है।

आदिवासी मुख्यमंत्री ने जगाया भरोसा, बदल रहा बस्तर

आभा मिश्रा

निदेशक, पॉलिसी वाच इंडिया फाउंडेशन

नक्सल उन्मूलन से समावेशी विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा बस्तर

औद्योगिक नीति 2024 से निवेश, विकास और विश्वास की मिली नई पहचान

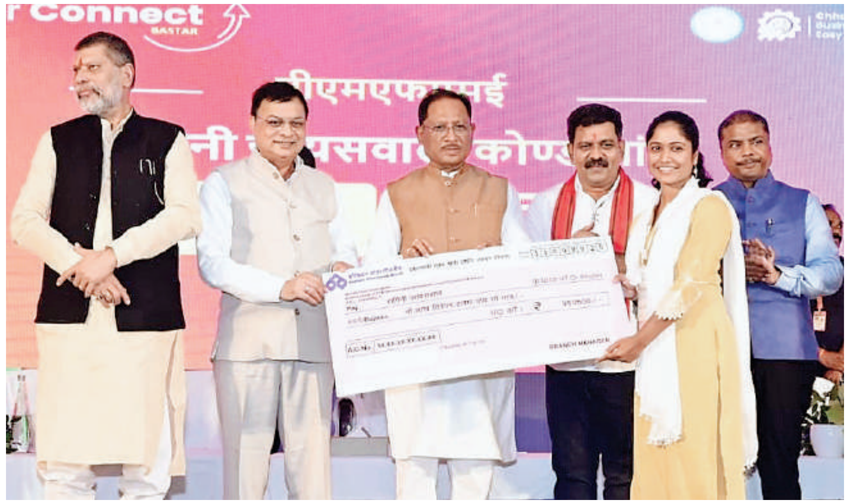

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का फैसला सफल होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से बस्तर अब भय और पिछड़ेपन से निकल कर विकास और विश्वास के नए धरातल पर खड़ा है और शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझने वाला यह क्षेत्र अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति प्रदेश के लोगों में बढ़ता भरोसा और केंद्र सरकार के नक्सल विरोधी अभियानों से न केवल इस क्षेत्र में उद्योग और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में बदलाव दिखने लगा है, बल्कि उम्मीद और विश्वास की नई किरण जगी है। पिछले 20 महीनों में मुख्यमंत्री बस्तर के 100 से अधिक इलाकों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों ने उन पर जनता का भरोसा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति

क्षेत्र में नक्सलवाद पर नियंत्रण ने विकास कार्यों की राह सुगम की है। इसी का नतीजा है कि बस्तर संभाग के जगदलपुर में पहली बार 350 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इस पर 550 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी क्रम में जगदलपुर में नवभारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 85 करोड़ रुपये के निवेश से 200 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और 33 करोड़ रुपये के निवेश से एक अन्य मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यहां पर 7.65 करोड़ रुपये के निवेश से नमन क्लब एवं वेलनेस सेंटर भी शुरू होने जा रहा है। इन परियोजनाओं से बस्तर में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वेलनेस का विस्तार होगा और सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां की जनता भी अब हिंसा से ऊब कर इस नए बदलाव को सहर्ष स्वीकार कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं डेयरी का नया युग

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और इसे धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार जरूरत के अनुसार नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने इस कमी की भरपाई करने की योजना बनाई और इसी के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर और कोण्डागांव जिलों में आधुनिक राइस मिल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जा रही है। नारायणपुर की पार्श्व एग्रीटेक कंपनी 8 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है जिससे 2400 टन प्रतिवर्ष परबॉयल्ड राइस का उत्पादन होगा। इसी तरह, कोण्डागांव में लावण्या उद्योग द्वारा 2.3 करोड़ रुपये के निवेश से मसाला ग्राइंडिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। बस्तर डेयरी फार्म 5.62 करोड़ रुपये के निवेश से डेयरी उत्पादों का उत्पादन और प्रसंस्करण करेगी। इन उद्योग इकाइयों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

निवेश का नया गढ़

बस्तर में कुल मिलाकर 967 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 2000 से अधिक स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर अन्य हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, पर्यटन, निर्माण, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर, कृषि यंत्र और शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में हो रहा निवेश बस्तर को एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। यह केवल उद्योगों का विस्तार नहीं, बल्कि 'नया बस्तर-बदलता बस्तर' की सजीव झलक है। कानून व्यवस्था की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार के बाद सरकार की स्कीमों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री की छवि इसमें प्रभावी साबित हो रही है क्योंकि आदिवासी समाज से आने की वजह से वह इस इलाके की जमीनी समस्याओं से वाकिफ हैं और उन्हीं के अनुरूप नीतियां बना रहे हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली या 1000 से अधिक रोजगार सृजित करने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस नीति में औषधि निर्माण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, आईटी एवं डिजिटल तकनीक, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस व डिफेंस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके तहत बस्तर में होटल, इको-टूरिज्म, वेलनेस सेंटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और खेल सुविधाओं जैसी परियोजनाओं पर 45 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। जबकि नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यह सरकार की सामाजिक पुनर्वास और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक अभिनव पहल के रूप में नई औद्योगिक इकाइयों में आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर पांच वर्षों तक उनके वेतन पर 40 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार की उद्योग नीति ने न सिर्फ बस्तर में, बल्कि पूरे प्रदेश में निवेश, नवाचार और रोजगार के लिए नए द्वार खोले हैं।■

(ये लेखक के निजी विचार हैं। लेख में व्यक्त विचारों के लिए युवा सहकार उत्तरदायी नहीं है)

नक्सल उन्मूलन और पुनर्वास नीति

केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य का बस्तर संभाग ही अब नक्सल गतिविधियों का केंद्र है। यहां भी दिसंबर 2023 से सुरक्षा बलों की लगातार आक्रामक रणनीति के परिणामस्वरूप नक्सल उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है।हाल ही में एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली के साथ दस नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले 453 माओवादी ढेर किये गए, 1616 गिरफ्तार किए गए और 1666 ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में न केवल नक्सलियों की गतिविधियों को कमजोर किया गया है, बल्कि विकास का माहौल भी तेजी से बन रहा है। पिछले 20 महीनों में 65 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं, जिनसे दुर्गम इलाकों में सुरक्षा का दायरा बढ़ा है और ग्रामीणों में आत्मविश्वास की भावना मजबूत हुई है।

आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के लिए घोषित नई पुनर्वास नीति ने उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का बेहतर अवसर प्रदान किया है। नई नीति में वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है और आवास व भूमि का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई नीति में आत्मसमर्पण करने वालों को तीन वर्षों तक प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्र में चार डिसमिल जमीन या ग्रामीण क्षेत्र में एक हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध कराने का फैसला विष्णु देव साय सरकार ने किया है। साथ ही, नक्सल मुक्त घोषित गांवों में एक करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों और हिंसा प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

एक इम्तिहान पास कर बाकी दो की तैयारी में जुटी हॉकी टीम

सत्येन्द्र पाल सिंह

पुरुष हॉकी एशिया कप जीतने के साथ ही विश्व कप 2026 के लिए किया सीधे क्वॉलिफाई

विश्व कप और एशियाड के लिए टीम में बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं, फुल्टन बने रहेंगे चीफ कोच

भारत ने राजगीर (बिहार) में उम्मीदों के मुताबिक पुरुष हॉकी एशिया कप जीत सीधे एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वॉलिफाई कर एक इम्तिहान पास कर लिया है। भारत अब अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप और एशियाड में दो और बड़े इम्तिहान पास करने की तैयारियों में जुट गया है। दुनिया में सातवें नंबर की हॉकी टीम ने पांच बार की चैंपियन रही दक्षिण कोरिया से अपना पहला सुपर 4 मैच ड्रॉ कराने के बाद उसे फाइनल में 4-1 से हराया। एशिया कप में सात में से छह मैच जीत कर भारत ने चौथी बार एशिया कप पर कब्जा किया।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकरों में से एक भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लंबे स्लैप शॉट और लंबे एरियल पास उन्हें दुनिया का विलक्षण खिलाड़ी बनाते हैं। भारत की खिताबी जीत का सबब अपने चीफ कोच क्रेग फुल्टन के मार्गदर्शन में स्ट्रक्चर पर काबिज रह प्रोसेस पर भरोसा करना रहा। भारतीय टीम ने पिछले लगातार दो ओलंपिक में कांसा जीत दर्शाया है कि वह एशिया की सबसे बड़ी हॉकी ताकत तो है ही, दुनिया की शीर्ष टीमों को भी टक्कर देने का दम रखती है। क्रेग फुल्टन कहते हैं कि भारतीय फैंस अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ जीतते देखना चाहते हैं। इस कारण बराबर जीत का दबाव रहता है। एशिया में धाक जमाने के बाद भारतीय टीम के सामने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरोपीय टीमों के खिलाफ धाक जमाने की चुनौती है।

कप्तान हरमनप्रीत और चीफ कोच फुल्टन की निगाहें अब 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप में पदक जिताने पर लगी हैं। 2026 में हॉकी विश्व कप 14-30 अगस्त और उसके बाद जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियाड होना है। विश्व कप और एशियाड में पदक जीतना भारत के लिए जरूरी है क्योंकि इससे वह 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक का टिकट पा लेगा। इनकी तैयारी के लिए बमुश्किल 11 महीने बाकी हैं। भारत अब सबसे पहले अजलान शाह कप खेलने मलेशिया जाएगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। फिर हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) है और ऑस्ट्रेलिया के भी भारत आने का कार्यक्रम है। इस बीच एफआईएच प्रो लीग 2025-26 भी शुरू हो जाएगी। भारत के लिए हॉकी विश्व कप की तैयारी का कुल मिला कर यह अच्छा मौका है। भारतीय टीम एक पखवाड़े के बाद सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट की तैयारी के लिए बेंगलुरु में जुटेगी।

भारत ने एशिया कप में अपने शुरू के दोनों पूल मैचों में चीन और जापान के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज की और दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहला सुपर 4 मैच बढ़त लेने के बावजूद कड़े संघर्ष से ड्रॉ कराया। तब आलोचकों ने चीफ कोच क्रेग फुल्टन की उनकी रणनीति को लेकर सवाल उठाए। फुल्टन ने तब भी यही कहा कि हारे या जीते, भारतीय टीम अपने 'स्ट्रक्चर' पर काबिज रहने के साथ बहुत जल्द अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने खेल को बेहतर करना जानती है। भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी कि वह अपने चीफ कोच की रणनीति को मैदान पर अमली जामा पहनाने में कमोबेश कामयाब ही रहती है।

कई हॉकी समीक्षकों और आलोचकों ने फुल्टन को हटाने तक की मांग करनी शुरू कर दी थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने एशिया कप के दौरान मुझसे बातचीत में साफ किया कि वह न तो चीफ कोच को हटाने और न ही टीम में किसी बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप और एशियाई खेलों के लिए चीफ कोच और चयनकर्ताओं से चर्चा कर एक ही भारतीय टीम चुनेंगे। तिर्की की मानें तो टीम के चयन में चयनकर्ता सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला फुल्टन की जरूरत के मुताबिक ही करेंगे। कुछ मिलाकर कोर ग्रुप के बाहर से किसी खिलाड़ी के टीम में शामिल होने की संभावना कम ही है। फुल्टन का चीफ कोच के रूप में करार 2028 के ओलंपिक तक है। पूरी उम्मीद है वह तब तक अपने पद पर काबिज रहेंगे।

भारत यदि एशिया कप नहीं जीतता तो उसे एफआईएच हॉकी विश्व कप में खेलने के लिए विश्व कप का क्वॉलिफायर खेलना पड़ता। उसमें नाकाम रहने पर विश्व कप में खेलने का सपना टूट सकता था भारत के नौजवान स्ट्राइकर अभिषेक नैन छह गोल कर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उनके जोड़ीदार सुखजीत सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी छह-छह गोल किए। शुरू के मैचों में अभिषेक का रिवर्स हिट से गोल करने में नाकाम रहने के बाद खुद डी के भीतर गोल करने की बजाय गोल करने के मौके बनाने और पेनल्टी कॉर्नर बनाने पर ध्यान लगाना भारतीय टीम के ज्यादा काम आया।■

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

अब फोकस विश्व कप पर: हरमनप्रीत

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का कहना है कि अब हमारा फोकस विश्व कप पर है। इसकी तैयारी के लिए हमारे पास करीब एक वर्ष है। एशिया कप में सभी खिलाड़ी पूरी तरह फोकस थे। इसे जीतना ही विश्व कप के लिए सीधे क्वॉलिफाई करने का रास्ता था। शुरुआती मैच हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन आखिरी के तीनों मैचों में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। इसने बतौर टीम हमारी क्षमता को फिर से स्थापित किया। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। दक्षिण कोरिया से सुपर 4 मैच ड्रॉ कराना एक झटका था और हम फाइनल में इससे उबरना चाहते थे। हमारे हर खिलाड़ी ने मजबूत किलेबंदी में योगदान किया। हमारे फॉरवर्ड ने पर्याप्त मौके बनाने के साथ उन्हें गोल में बदला।

"विश्व कप और एशियाई खेलों जैसे दो बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करने से पहले टीम मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। इसके बाद एचआईएल और एफआईएच प्रो लीग में खेलेगी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एशिया कप में हमारी टीम शुरूआत से ही चैंपियन की तरह खेली। मलेशिया के खिलाफ मैच को क्वॉर्टर फाइनल और चीन के खिलाफ मैच को सेमीफाइनल की तरह खेले। हमने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं।"

क्रेग फुल्टन
चीफ हॉकी कोच

युवाओं की नौकरी के लिए निजी कंपनियों से एमओयू

युवा सहकार टीम

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर युवाओं की रोजगार क्षमता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों मेंटर टुगेदर और क्विकर से एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और निजी क्षेत्र के रोजगार के बीच की खाई को पाटने के सरकार के दृष्टिकोण को और मजबूत करना है। ये एमओयू भविष्य के अनुरूप रोजगार मॉडल को दर्शाती हैं जो डिजिटल, समावेशी और सम्मानजनक है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

डॉ. मांडविया ने इस अवसर कहा कि लगभग 52 लाख पंजीकृत नियोक्ताओं, 5.79 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 7.22 करोड़ से अधिक रिक्तियों के साथ एनसीएस प्लेटफॉर्म अब न केवल नौकरी लिस्टिंग प्रदान करने के लिए, बल्कि सभी रोजगार संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में पोर्टल पर 44 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में मंत्रालय ने अमेजन और स्विगी सहित दस प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों से अब तक लगभग पांच लाख रिक्तियां उपलब्ध हो चुकी हैं।

युवाओं पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित किए जाने का उल्लेख करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट वाली पांच प्रमुख योजनाओं के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का एक प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) है जिसके लिए 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ युवा पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे।

- ❑ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मेंटर टुगेदर और क्विकर के साथ किया एमओयू
- ❑ एनसीएस पोर्टल के माध्यम से नौकरी तक पहुंच और करियर मार्गदर्शन बढ़ाने के लिए समझौता

मेंटर टुगेदर के साथ साझेदारी के पहले वर्ष में ही दो लाख युवाओं तक पहुंच की उम्मीद है जिनमें एक लाख एनसीएस और एक लाख प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के प्रतिभागी शामिल हैं। यह शहर और जिला स्तर पर पहुंच के साथ व्यक्तिगत करियर मार्गदर्शन प्रदान करेगा ताकि कोई भी नौकरी चाहने वाला पीछे न छूटे। यह पहली बार नौकरी चाहने वालों, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वालों को 24 हजार से अधिक प्रशिक्षित पेशेवरों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करेगा।

क्विकर के साथ समझौते से क्विकर जॉब्स से 1200 से ज्यादा शहरों में प्रतिदिन 1,200 से ज्यादा नौकरियों की सूची को एनसीएस पोर्टल में एकीकृत करके रोजगार तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। इस सहयोग से लाखों इच्छुक लोगों, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच का विस्तार होगा।

शोभा करंदलाजे ने इस अवसर पर कहा कि एनसीएस डिजिटल रोजगार सुविधा के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। यह एक ही स्थान पर नौकरी मिलान, परामर्श और कौशल विकास प्रदान करता है। यह साझेदारी न केवल युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी।■

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING FARMERS TO GROW BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone:** 011-29243412
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.

Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.

Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B, Vardhman Janak Market, Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, letls build a brighter financial future!